



स्त्री- विमर्श

विस्थापन और आदिवासी स्त्री

डॉ. स्नेह लता नेगी
सहायक प्रो. हिन्दी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
मो. 8586066430

भारत में हर आदिवासी समुदाय की अपनी भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, इतिहास और सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं। आदिवासी स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी देखने की जरूरत है। आदिवासी समाज की विविध भाषा, संस्कृति और इतिहास है ऐसे में स्त्रियों से जुड़ी बहुत सी समस्याएँ सभी आदिवासी समाज में कमोबेश एक जैसे हैं जिसका संबंध हर आदिवासी स्त्री से है। लंबे समय की अंग्रेजी हुकुमत हो या आज की पूंजीवादी व्यवस्था का दमन-शोषण, इन सबसे आदिवासी स्त्रियाँ सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं।

अंग्रेजों के आगमन से पहले यहाँ के गैर आदिवासी लोगों ने आदिवासियों को उनके उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों से खदेड़ कर उन्हें दुर्गम पहाड़ों-जंगलों की ओर पलायन करने के लिए विवश किया। उन दुर्गम पहाड़ों जंगलों में भी श्रमशील आदिवासियों ने अपने अनुकूल और स्वतंत्र समाज को विकसित किया। विस्थापन की इस प्रक्रिया को रामायण जैसे महाग्रंथों में भी देखा जा सकता है जहाँ आदिवासी, मनुष्य की गिनती में ही नहीं है। इस तरह की भेदभाव पूर्ण दृष्टि हमारे इतिहास में देखी जा सकती है। अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण तंत्र के साथ ही आदिवासियों के संसाधनों का दोहन तेज गति से





होने लगता है। ये अंग्रेजों के लिए अपनी पूँजीवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का सुअवसर भी था। जिसका परिणाम यह हुआ कि आदिवासी अपने ही प्राकृतिक संसाधन, जल-जंगल-जमीन से बेदखल होने लगे। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की जमीन पर व्यवसायिक फसलें उगाई जाने लगीं जिसमें अंग्रेजों को अधिक से अधिक लाभ हो। “वन तथा खनिज संपदा के दोहन, व्यवसायिक फसलों के लिए चाय कॉफी और रबड़ के बागानों के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। अपने जंगल-जमीन से उजड़े ये आदिवासी सस्ते मजदूर की भूमिका में खपाए गए। अंग्रेजी साम्राज्यवादी व्यवस्था की खुशहाली के लिए आवश्यक था कि आदिवासी व्यवस्थाएँ समूल उखाड़ी जाएँ।”¹ अंग्रेज जानते थे कि आदिवासी ईमानदारी, साहसी और लड़ाकू कौम है जो अन्याय के विरुद्ध अगर संगठित हो गए तो उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं इसलिए उन्हें अपने

स्थान से विस्थापित करना ज़रूरी है। संस्थानों पर भी आप तब तक कब्जा नहीं कर सकते जब तक उन्हें खदेड़ेंगे नहीं, उन्हें हीन साबित नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने कूटनीतिक ढंग से यह सब किया और विस्थापन का सिलसिला चलता रहा।

अपनी जड़ों से उखड़ने और विस्थापन का खामियाज़ा सबसे ज्यादा आदिवासी स्त्रियों को उठाना पड़ा। आदिवासी स्त्री परिवार समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। विस्थापन के साथ धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था की उत्पादन प्रक्रिया में उसकी भूमिका सिमटने लगी और पुरुषों के साथ खेत-खलिहान छोड़ चाय बागानों, खदानों और फैक्ट्रियों में मजदूरी के लिए सिर पर गठरी में अपनी गृहस्थी समेटे एक जगह से दूसरी जगह भटकने को मजबूर होने लगी। कारखानों, खदानों का वातावरण बच्चों और स्त्रियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनुकूल नहीं होता था। “विस्थापन के कारण अनेक ग्रामीण और आदिवासी समुदाय



न केवल बेघर हुए बल्कि उन्हें अपने परंपरागत पेशों से भी वंचित होना पड़ा। खासकर आदिवासी स्त्रियाँ जो प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह निर्भर थी। विस्थापन के बाद दूसरों के घरों में नौकरानी बनने को विवश हो गयी।²

विस्थापन ने आदिवासियों से उनके संसाधन ही नहीं छीने बल्कि उनकी कला, संस्कृति और इतिहास को भी नष्ट कर दिया। विस्थापन के बाद स्त्रियाँ अपने पति पर आश्रित रहने लगीं और बाहरी समाज के साथ आदिवासी समाज के संपर्क में आने के साथ-साथ दीकुओं की पितृसत्तात्मक मानसिकता धीरे-धीरे आदिवासी समाज के पुरुषों पर भी असर करने लगी। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर आदिवासी समाज पितृसत्तात्मक समाज है लेकिन हिंदू पितृसत्तात्मक समाज की तरह दमन शोषण के मापदंडों की तरह नहीं और न ही दमन-शोषण

को वंश या शास्त्रीय आधार प्राप्त है। पितृसत्तात्मक समाज होने पर भी स्त्री पुरुष में बराबरी का दर्जा इस समाज की अमूल्य धरोहर है। जैसे-जैसे मुख्य धारा से संपर्क हुआ आदिवासी समाज की स्त्रियों के प्रति मुख्यधारा की सीमित समझ और दृष्टि अपने ही मापदंडों में देखने की आदी मुख्यधारा के पुरुषों के दमन और शोषण का शिकार आदिवासी स्त्रियाँ होती रही हैं। यह मुख्यधारा का संकीर्ण दृष्टिकोण ही है जो उनके घोंटुल और भगोहरिया जैसी पारंपरिक प्रथा को भी यौन संबंधों को बनाने के केन्द्र के रूप में देखता है।

1990 के बाद भूमण्डलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया के चलते आदिवासियों का विस्थापन और तेजी से होने लगा। सरकार राष्ट्रहित के नाम पर कॉरपोरेट घरानों को आदिवासियों की जमीन औने-पौने दामों में बेचकर आदिवासियों के भविष्य के साथ



खिलावाड़ कर रही है। देश का यह कैसा विकास है, समझने की जरूरत है जहाँ एक के विकास के लिए दूसरे के जीवन को खतरे में डालना पड़े। हद तो तब हो जाती है जब विस्थापितों के लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था सरकार नहीं करती है। रोज केरकेट्टा की चिंता इस संदर्भ में उल्लेखनीय है “जो सबसे ज्यादा निराशाजनक है वह यह है कि संसद और विधान सभाओं में जनता द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधियों ने कभी भी अपने क्षेत्र से पलायन करने वाली जनता की सुध नहीं ली यह खेद की बात है कि आम आदमी के पास जीवन के प्रति दूर दृष्टि नहीं है। लेकिन उससे भी अधिक निराशाजनक यह है कि इन प्रतिनिधियों के पास तक दूर दृष्टि का अभाव है।”³ निश्चित ही आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधि ही उनके लिए काम नहीं करेगा तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है।

विस्थापन ने आदिवासी स्त्रियों की आजीविका ही नहीं छीनी बल्कि स्त्रियों में सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी असुरक्षा का भाव पैदा किया है। “विस्थापन स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अलग तरह से प्रभावित करता है। इसके अनेक कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख है स्त्रियों का ज़मीन, प्राकृतिक संसाधनों तथा अपने परिवेश के साथ घनिष्ठ संबंध होना जो न केवल उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का निर्धारण करता है, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।”⁴ आदिवासी स्त्रियों का अपने परिवेश से करीबी रिश्ता होता है अपने पैतृक समाज के नजदीक रहना उसे विपरीत परिस्थितियों में आत्मबल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जिससे विस्थापन के बाद वह वंचित हो जाती है। आदिवासी सामूहिक जीवन में विश्वास रखता है जो उस समाज का जीवन दर्शन है। आदिवासी सामूहिक है इसलिए समाज



की व्यवस्था पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। जहाँ स्त्रियों की सुरक्षा, अधिकार और न्याय की समुचित व्यवस्था रहती थी। वहाँ विस्थापन ने उस सामाजिक नियंत्रण को लगभग खत्म कर दिया और आज विस्थापित आदिवासी स्त्रियाँ घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार झेलने को विवश हैं। इसके अतिरिक्त विस्थापन विरोधी स्त्रियों को पुलिस प्रशासन की मार भी झेलनी पड़ी।

आदिवासी अर्थव्यवस्था में आदिवासी संस्कृति के संरक्षण में आदिवासी स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतिहास गवाह है कि अपनी संस्कृति, जल-जंगल-ज़मीन को बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर लेने वाली आदिवासी क्रांतिकारी स्त्रियाँ फूलों, झानो, माकी और सिनगी दर्ई जैसी स्त्रियों की कुर्बानी अविस्मरणीय है। विस्थापन के इस दौर में भी हमें एकजुट होकर फूलों, झानों और सिनगी दर्ई जैसी साहसी बनने की जरूरत है। जैसे-जैसे विस्थापन

की प्रक्रिया बढ़ने लगी विस्थापन के विरोध और सुव्यवस्थित पुनर्वास की माँग को लेकर आंदोलन बढ़ने लगे। ओडिशा में पॉस्को परियोजना और गुजरात में नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन इसका ज्वलंत उदाहरण है। “विकास और विस्थापन के पूरे ताने बाने के भीतर स्त्रियों, खासकर ग्रामीण और आदिवासी स्त्रियों की स्थिति को ही सामने लाना है। तथ्य बताते हैं कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना कानून आदिवासियों तथा वनवासियों के अधिकारों को कानूनी जामा पहनाने वाला अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम, (वन्य अधिकार अधिनियम), 2006 की माँग को लेकर चले लंबे आंदोलन में भी स्त्रियों ने निर्णायक योगदान दिया था। केवल यही नहीं 1970-80 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए चिपको आंदोलन में गौरा देवी समेत बहुत सी स्त्रियों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।”⁵ जब से





आदिवासियों के संसाधनों और जंगल-जमीन पर दबाव बढ़ने लगे। तब से अपने संसाधनों को संरक्षित करने की मुहिम भी तेज होने लगी। आदिवासी स्त्रियाँ ही अपने पर्यावरण संस्कृति और

संसाधनों की संरक्षिका है। वैसे भी आदिवासी स्त्रियों के विस्थापन के विरुद्ध और भावी पीढ़ी की सुरक्षित और स्थाई भविष्य के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है।

संदर्भ

1. भारत में स्त्री असमानता, गोपा जोशी, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, सं. 2015, पृ. 18
2. प्रतिमान, जनवरी-जून 2015, अंक-1, संपा. अभय कुमार दुबे, पृ. 223
3. स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति, रोज केरकेट्टा, प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन, राँची 2014, पृ. 47
4. प्रतिमान, जनवरी-जून 2015, अंक-1, संपा. अभय कुमार दुबे, पृ. 229
5. वही, पृ. 224
6. भारत की क्रांतिकारी आदिवासी औरतें, वावसी किडो संपा. रमणिका गुप्ता, रमणिका फाउंडेशन, 2014